

New Indian Express

### **NHRC to investigate 'fake' police encounter**

<https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2023/jan/15/nhrc-to-investigate-fake-police-encounter-2538089.html>

Alleging that the police had branded them as Maoists to give it an impression of encounter, petitioner Radhakanta Tripathy had moved the NHRC for justice.

BHUBANESWAR: The National Human Rights Commission (NHRC) has decided to investigate the alleged fake encounter of two civilians at Boipariguda in Koraput district. Koraput police had gunned down two tribals in Malipadar forests under Boipariguda limits on November 11 which was later alleged to be a fake encounter after the family members of slain tribals asserted that the two were daily wagers.

Acting on a petition, the apex human rights panel has asked its director general (investigation) to examine the records/reports available on the case and submit the findings within four weeks. Earlier, reports were sought from the DG of Police and collector and SP of Malkangiri on the alleged fake encounter. Though all reports are yet to be received, the commission in its recent order stated that the case required to be analysed by the investigation division on the existing materials to come to the conclusion whether there is any violation of human rights by any public servant.

The two tribals killed in the 'encounter' were Dhana Khamar of Sargiguda village under Malkangiri police limits and Jaya Kumar Nag of Nuagada under Kosagumuda police limits in Nabarangpur. Alleging that the police had branded them as Maoists to give it an impression of encounter, petitioner Radhakanta Tripathy had moved the NHRC for justice.

The commission has also received another complaint from an activist Sagar Jena and an intimation from the superintendent of Kantabanji sub-jail regarding the death of high profile under trial prisoner Gobinda Sahu, the prime accused in Kalahandi lady teacher Mamita Meher murder case. Sahu was found hanging from the kitchen window of Kantabanji sub-jail on December 20.

Taking cognizance of the matter, the NHRC has directed the Balangir collector and SP and superintendent of Kantabanji sub-jail to send the magisterial enquiry report, crime branch report along with the postmortem and other enquiry reports within six weeks. The commission has also asked its registrar to take up the matter with the Odisha State Human Rights Commission to inquire whether they have taken cognizance of the case of death in jail custody.

# इटावा के सिपाही की पीड़ा का आयोग ने लिया संज्ञान

कानपुर। सिपाही पिता सोनू चौधरी का बेटे के शव को लेकर एसएसपी ऑफिस जाने का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। इटावा की इस घटना पर कानपुर के इंजीनियर व सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार सिंह ने आयोग से जांच की मांग करते हुए पीड़ित सिपाही को मुआवजा दिलाने की मांग की है। आयोग ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार भी कर लिया है।

पंकज ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इटावा की इस घटना की जानकारी भेजी है जिसमें सिपाही को बीमार पत्नी कविता की देखभाल के

## मानवाधिकार आयोग को वाद में क्या बताया

सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार सिंह ने वाद में कहा कि घटना से प्रार्थी बेहद चिंतित, परेशान और दुःखी है। जिन पर लॉ एण्ड ऑर्डर की जिम्मेदारी रहती है और जिनके कारण आम जनता को सुरक्षा का अहसास होता है, वही जवान सुविधाओं से वंचित हैं। सिपाही अवकाश के रूप में अपना अधिकार मांग रहा था। उसे पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के लिए छुट्टी नहीं मिल सकी। यह पूरे सिस्टम की नाकामी और लापरवाही है। लोकतंत्र में पुलिस का सिपाही अपने हक से महरूम है। यही सुविधाएं न मिलने से नकारात्मकता आती है जो कभी-कभी जनता के बीच दिखती है।

लिए अवकाश नहीं मिल सका। इस दौरान छोटा बेटा हर्षित घर से बाहर चला गया और जलभराव वाले किसी स्थान पर गिर गया। वहां डूबने से उसकी मौत हो गई। सिपाही मथुरा का रहने वाला है और वेदपुरा में तैनात है।

**बैरक कांड में दिलाएंगे इंसाफ:** अगस्त 2020 में कानपुर पुलिस लाइन में बैरक कांड हुआ था। इसमें एक की जान गई थी और कई घायल हो गए थे। इसके खिलाफ पंकज कुमार सिंह ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में वाद दाखिल किया था। अब भी इस मामले में सुनवाई जारी है। आयोग ने घटना पर कई बार प्रतिकूल टिप्पणी भी की।

Janserishta

## ओडिशा का हीराकुंड बांध 66वें साल में प्रवेश, विस्थापितों के लिए मुआवजे की लड़ाई जारी

<https://jantaserishta.com/local/odisha/odishas-hirakud-dam-enters-66th-year-but-fight-for-compensation-continues-for-the-displaced-1930635>

संबलपुर: ओडिशा का हीराकुंड बांध, जिसे दुनिया का सबसे लंबा बड़ा मिट्टी का बांध कहा जाता है, ने 65 साल पूरे कर लिए हैं और राज्य में विकास के सबसे बड़े हॉलमार्क में से एक के रूप में खड़ा है, इसलिए हजारों परिवारों के मुआवजे और पुनर्वास की लड़ाई है। परियोजना के दौरान विस्थापित हुए थे। महानदी नदी पर 1957 में उद्घाटन किए गए, हीरादूद बांध को आज "आधुनिक भारत के मंदिर" के रूप में देखा जा सकता है, जैसा कि पूर्व प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लेकिन यह उन सभी लोगों के दुख का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिनके मुआवजे और पुनर्वास की प्रतीक्षा यहां तक कि अनसुलझी है। छह दशकों के बाद। जबकि ओडिशा सरकार ने आज जलाशय के 66वें वर्ष का जश्न मनाया, बांध के आने से उजड़ गए परिवारों की पीढ़ियों के विस्थापन और नुकसान की यादें सता रही हैं।

उस दिन, हीराकुंड बांध बिष्टपीठ कल्याण समिति के सदस्यों ने आरडीसी उत्तर के कार्यालय के बाहर धरना दिया और फिर मांगों की सूची को लेकर उनके आवासीय कार्यालय की ओर एक रैली की। मांगों में सरकार द्वारा आश्वासन के अनुसार 10 डिसमिल जमीन, कृषि भूमि का बंदोबस्त, एनएचआरसी के आदेशों को लागू करना, विस्थापन का प्रमाण और लखनपुर तहसील कार्यालय में तीन अतिरिक्त तहसीलदारों और पांच क्लर्कों की नियुक्ति शामिल है, समिति अध्यक्ष सेलबाला प्रधान ने बताया।

रिपोर्टों के अनुसार, परियोजना से लगभग 26,501 परिवार प्रभावित हुए थे, जिनमें से 19,000 विस्थापित हुए थे। इन वर्षों में, केवल 2,243 परिवारों को 17 पुनर्वसन कॉलोनियों में स्थानांतरित किया गया है जबकि अन्य ने न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी है। मानवाधिकार वकील राधाकांत त्रिपाठी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में यह आरोप लगाया कि 26,000 से अधिक बेदखलियों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, शीर्ष निकाय ने विस्थापितों की दुर्दशा का उचित संज्ञान लेने के लिए ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया था।

राजस्व संभागीय आयुक्त (आरडीसी), उत्तरी मंडल, ओडिशा ने एनएचआरसी के नोटिस के जवाब में कहा था कि संबलपुर, बरगढ़, झारसुगुड़ा और सुबरनपुर जिलों में विस्थापित परिवारों की शिकायतों को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन आधिकारिक सूत्रों ने बाद में स्वीकार किया कि वहां ऐसे बहुत से परिवार थे, जिनका मुआवजा और ज़मीन का बंदोबस्त अभी बाकी था। राज्य सरकार ने 10 डिसमिल भूमि, विभिन्न चरणों में मुआवजे की राशि का आश्वासन दिया था लेकिन परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा दावा किए जाने पर अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

ABP News

### **Agra News: 'महिला के शव का लेडी डॉक्टर ही करे पोस्टमॉर्टम', जज ने CMO को लिखा लेटर**

<https://www.abplive.com/states/up-uk/agra-news-judge-gyanendra-tripathi-wrote-letter-to-cmo-about-women-doctors-should-do-female-body-postmortem-ann-2308216>

UP News: अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान महिला की बॉडी के सारे कपड़े उतार कर पूरी प्रक्रिया की जाती है। इसलिए यह महिलाओं की आबरू के साथ खिलवाड़ है।

Agra News: आगरा (Agra) में तैनात अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने एक लेटर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण श्रीवास्तव को इस बाबत लिखा है कि महिलाओं के शव का पोस्टमार्टम महिला डॉक्टर और महिला पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा ही किया जाए। उनके मुताबिक महिला के आबरू की रक्षा की जानी चाहिए। फिर चाहे मौत से पहले हो या मौत के बाद। जज ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने एक महिला अधिवक्ता प्रमिला शर्मा द्वारा लिखी गई चिट्ठी के क्रम में यह निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को जारी किए हैं।

जज ज्ञानेंद्र त्रिपाठी के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान महिला की बॉडी के सारे कपड़े उतार कर पूरी प्रक्रिया अमल में लाई जाती है। इसलिए यह महिलाओं की आबरू के साथ खिलवाड़ है। जब जीते जी आबरू का ध्यान रखा जाता है तो मरने के बाद भी आबरू का उतना ही ध्यान रखा जाए। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी समय-समय पर माना है कि शव की भी अपनी गरिमा होती है।

**महिला के शव का लेडी डॉक्टर ही करे पोस्टमॉर्टम'**

इसको लेकर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ज्ञानेंद्र त्रिपाठी कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में व्यवस्था दी है जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जीवित व्यक्तियों को ही प्राप्त नहीं है बल्कि यह मृत व्यक्तियों के संबंध में भी है। कोरोना काल में भी शवों के साथ अपमानजनक व्यवहार को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। ऐसे में किसी व्यक्ति को जीवित रहते या मरने के उपरांत उसके शव का गरिमापूर्ण व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकारों की श्रेणी में आता है।

वहीं इस मुद्दे की ओर ध्यानाकर्षित करने वाली अधिवक्ता और समाजसेवी प्रमिला शर्मा कहती हैं कि जिला स्तर पर पर्याप्त महिला स्टाफ रहता है और ऐसे में आसानी से महिला शव के पोस्टमार्टम के लिए महिला डॉक्टर और महिला स्टाफ आसानी से उपलब्ध हो सकता है। इस प्रक्रिया को अमल में लाए जाने से मरने के बाद भी महिला के गरिमा की रक्षा की जा सकेगी। वहीं इसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि जो निर्देश उनको प्राप्त हुए हैं, उसके क्रम में महिला शव का पोस्टमार्टम महिला डॉक्टर और स्टाफ द्वारा आगे से कराया जाए और इसके लिए व्यवस्था बनाई जायेगी।

Janserishta

## महिला अधिवक्ता पर हमला: आरोपी की मां ने एनएचआरसी से संपर्क किया

<https://jantaserishta.com/local/manipur/attack-on-woman-advocate-accuseds-mother-approaches-nhrc-1929263>

महिला अधिवक्ता पर कथित हमले के मामले में आरोपी की मां ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि वह मणिपुर मानवाधिकार आयोग (एमएचआरसी) से कोई समर्थन प्राप्त करने में विफल रही है। 10 जनवरी, 2023 को एक महिला वकील पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में इंफाल पश्चिम के थांगमीबंद मैसनाम लीकाई के एल जिबनकुमार के 27 वर्षीय बेटे लोंगजाम रोहित को शुक्रवार को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

आरोपी नांगबाम गनीबाला देवी की मां ने शुक्रवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि मणिपुर मानवाधिकार आयोग ने उसकी मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिवक्ता उनके बेटे का मामला लेने के लिए तैयार नहीं था। एनएचआरसी को दी गई एक शिकायत में, उसने कहा कि वह कई अधिवक्ताओं से मिलीं, जिनमें ज्यादातर महिला वकील थीं और यहां तक कि अदालत कक्ष में भी गई, जहां उसके बेटे को पुलिस हिरासत में तीन दिन पूरे करने के बाद लाया जाना था। लेकिन कई अधिवक्ताओं ने अदालत पर उसके बेटे को न्यायिक हिरासत में भेजने का दबाव बनाया।

कोई अन्य विकल्प न होने पर, वह एमएचआरसी कार्यालय गई और अधिकारियों में से एक से अपने बेटे का कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। लेकिन अधिकारी ने कहा कि एमएचआरसी कोई कार्यवाही शुरू नहीं कर सका, हालांकि उसने शिकायत दर्ज की थी क्योंकि एमएचआरसी के पास इस समय कोई अध्यक्ष और सदस्य नहीं है। मां को एमएचआरसी से कोई मदद नहीं मिली। कुछ देर बाद उसके बेटे को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। उसे बताया गया कि उसके बेटे के खिलाफ आईपीसी की और भी कड़ी धाराएं जोड़ी गई हैं।

इसलिए, उन्होंने NHRC से आग्रह किया कि वह सचिव, ऑल मणिपुर बार एसोसिएशन को उनके बेटे के कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार को कम न करने का निर्देश दें, पुलिस महानिदेशक, मणिपुर को महिला पुलिस स्टेशन, इंफाल के कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश दें। पश्चिम ने अपने बेटे के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने और मणिपुर के पुलिस महानिदेशक को किसी अन्य पुलिस अधिकारी को जांच सौंपने और घटना के तथ्यों को स्थापित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज का संग्रह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

अपने बयान में, उसने कहा कि 10 जनवरी, 2023 को सुबह लगभग 11 बजे, उसका बेटा लोंगजाम रोहित और उसका दोस्त सुहैमथाई नागमपाल फौगीशांगबम लीकाई सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। उसका बेटा पिलर सवार था। नागमपाल रोड पर भारी ट्रैफिक था। ट्रैफिक जाम के बीच, गलती से, उनके वाहन ने नोंगमैथेम तेजप्रिया द्वारा संचालित एक काले रंग के वेस्पा (स्कूटर) को थोड़ा टक्कर मार दी, जिसने बाद में खुद को एक वकील के रूप में पहचाना।

उक्त दुर्घटना में कोई चोट नहीं आई थी, उसने कहा, जब उसका बेटा उससे बात करने के बाद वहां से जाने वाला था, तेजप्रिया ने अपने बेटे और उसके दोस्त पर उसके वाहन को टक्कर मारने का आरोप लगाते हुए प्लेजर वाहन की चाबी छीन ली। उसने कहा कि उसके बेटे ने उससे चाबी वापस करने का अनुरोध किया क्योंकि उसके बेटे और उसके दोस्त दोनों को एक जरूरी काम में शामिल होना था।

"मेरे बेटे ने यह भी कहा कि उसने (तेजप्रिया) वाहन के पंजीकरण संख्या की एक तस्वीर ली ताकि वे बाद में मामले को सुलझा सकें। इस पर, तेजप्रिया ने अपने दोस्त का कॉलर (शर्ट) पकड़ लिया और उसके हाथ इधर-उधर खींच लिए।" मां ने कहा कि मौके पर दृश्य देखकर उसके बेटे और राहगीरों ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की, जब उसके बेटे ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो उसने अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और कहा कि वह एक वकील है। उसके बेटे और उसके दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज करेगी।

काफी कहासुनी के बाद तेजप्रिया ने वाहन की तस्वीर ली और आखिरकार राहगीरों के हस्तक्षेप से उसके बेटे और उसके दोस्त को जाने दिया गया। उसी दिन शाम करीब 4 बजे महिला थाने लम्फेल के कुछ पुलिसकर्मी उनके आवास पर आए और पुलिस टीम उनके बेटे को साथ ले गई। वह अपने पति के साथ थाने पहुंची जहां उसके बेटे को हिरासत में ले लिया गया। उसने यह भी कहा कि उन्होंने तेजप्रिया को पुलिस स्टेशन में पाया और उन्होंने उससे मामले को निपटाने का अनुरोध किया।

थाने में तेजप्रिया ने अपने बेटे पर अपने खिलाफ भीड़ के हमले के लिए उकसाने का आरोप लगाया। तेजप्रिया के कहने पर महिला पुलिस ने आईपीसी की धारा 354/509 के तहत प्राथमिकी संख्या 02(01)2023 दर्ज की। 11 जनवरी को उसके बेटे को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इंफाल वेस्ट-1 के सामने पेश किया गया।

पुलिस ने तीन दिन का रिमांड मांगा। सुनवाई के दौरान, उसके बेटे के वकील ने एक वीडियो क्लिपिंग दिखाई, जिसमें कथित घटना को एक मोबाइल फोन से कैद किया गया था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि तेजप्रिया ने ही इस घटना को उकसाया और घटना को देखने वाले राहगीरों ने भी उसे अपने मासूम बेटे पर आरोप लगाने के लिए डांटा। उसके बेटे की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई और उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। उसने कहा कि वह अपने बेटे से पुलिस स्टेशन में मिली थी और उसके बेटे ने उसे बताया कि उसे हिरासत में प्रताड़ित किया गया था।

13 जनवरी, 2023 को, ऑल मणिपुर बार एसोसिएशन के सचिव ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया था कि "सभी सदस्य 13 जनवरी, 2023 को सुबह 11.30 बजे से अदालत के अंत तक एन के प्रति एकजुटता दिखाते हुए अपने-अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। मारपीट की शिकार अधिवक्ता तेजप्रिया देवी

## इटावा के सिपाही की पीड़ा का आयोग ने लिया संज्ञान

कानपुर। सिपाही पिता सोनू चौधरी का बेटे के शव को लेकर एसएसपी ऑफिस जाने का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। इटावा की इस घटना पर कानपुर के इंजीनियर व सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार सिंह ने आयोग से जांच की मांग करते हुए पीड़ित सिपाही को मुआवजा दिलाने की मांग की है। आयोग ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार भी कर लिया है।

पंकज ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इटावा की इस घटना की जानकारी भेजी है जिसमें सिपाही को बीमार पत्नी कविता की देखभाल के लिए अवकाश नहीं मिल सका। इस दौरान छोटा बेटा हर्षित घर से बाहर चला गया और जलभराव वाले किसी स्थान पर गिर गया। वहां डूबने से उसकी मौत हो गई।

Janserishta

## ओडिशा की रायगढ़ा जेल से रिहा होने के बाद गर्भवती महिला की मौत हो गई

<https://jantaserishta.com/local/odisha/pregnant-woman-dies-after-being-released-from-odishas-rayagada-jail-1928376>

एक गर्भवती महिला, जिसे गिरफ्तार कर 16 दिनों तक ओडिशा के रायगढ़ा जेल में रखा गया था, उसकी रिहाई के एक दिन बाद प्रसव के बाद की जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई। उसके परिवार ने दावा किया कि मैकांच पंचायत के अंदराकांच गांव की रहने वाली और एक दिहाड़ी मजदूर की पत्नी तीस वर्षीय सुलबती नाइक की बुधवार और गुरुवार की दरम्यानी रात मौत हो गई। परिवार ने कहा कि नौ महीने की गर्भवती सुलबती उन 13 महिलाओं में शामिल हैं जिन्हें पुलिस ने पिछले साल 26 दिसंबर को एक निजी कंपनी में नौकरी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, क्योंकि वे इसके आसपास रहती हैं।

मंगलवार शाम को जेल से बाहर आने के तुरंत बाद उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसे जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया। महिला के पति बैद्य नाइक ने कहा कि बुधवार रात महिला ने एक बेटे को जन्म दिया और उसकी हालत बिगड़ने पर उसे एसएलएन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जो कि अंदराकांच से करीब 70 किलोमीटर दूर था। उन्होंने बताया कि कोरापुट अस्पताल ले जाते समय देर रात करीब डेढ़ बजे महिला की मौत हो गयी।

बैद्य ने कहा कि शिशु को रायगढ़ा अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में निगरानी में रखा गया है। उसके रिश्तेदार तुलसी नाइक ने कहा कि काशीपुर की एक अदालत द्वारा उसकी जमानत खारिज किए जाने के बाद महिला को जेल हिरासत में भेज दिया गया था क्योंकि पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) सहित अन्य के तहत आरोप लगाए थे। उनके पति ने कहा, "2 जनवरी को अदालत के फिर से खुलने के बाद, हमने जमानत अर्जी दायर की थी, लेकिन इसमें देरी हुई क्योंकि पुलिस ने दो अलग-अलग पुराने मामलों में उसकी रिमांड मांगी थी। आखिरकार मंगलवार (10 जनवरी) को उसकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली गई।"

तुलसी ने कहा, "वैद्य दिहाड़ी मजदूर है और दंपति की 10 साल की एक बेटी भी है। हम सरकार से शोक संतप्त परिवार के लिए पर्याप्त मुआवजे की मांग करते हैं।" संपर्क करने पर एसपी (रायगढ़) विवेकानंद शर्मा ने कहा, "मामले को देखा जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।" कोरापुट के कांग्रेस सांसद सप्तग्री उलाका ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, "पुलिस गर्भावस्था के उन्नत चरण में एक महिला को कैसे गिरफ्तार कर सकती है, वह भी हत्या के प्रयास के आरोप में? इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए।" उलाका ने यह भी सवाल किया कि क्या जेल में रहने के दौरान महिला को पर्याप्त चिकित्सा सहायता प्रदान की गई थी और इसकी जांच की जरूरत है। उन्होंने कहा, "हम शोक संतप्त परिवार के लिए एक करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप की मांग करेंगे।"

Dainik Bhaskar

**'आगरा में महिला का पोस्टमॉर्टम लेडी डॉक्टर ही करेगी':कोर्ट ने आगरा CMO को आदेश दिया, अब तक पुरुष डॉक्टर और फार्मासिस्ट ही करते आए**

<https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/agra/news/court-orders-now-only-lady-doctors-will-do-post-mortem-of-women-in-agra-130797970.html>

आगरा में महिलाओं की डेडबॉडी का पोस्टमॉर्टम अब पुरुष डॉक्टर्स और स्टाफ नहीं कर सकेंगे। कोर्ट ने इस बारे में सीएमओ को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि किसी भी महिला की डेडबॉडी का पोस्टमॉर्टम लेडी डॉक्टर्स द्वारा किया जाएगा। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता प्रमिला शर्मा द्वारा कोर्ट में पत्र प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि आगरा में मृत महिलाओं के शव का पोस्टमॉर्टम पुरुष डॉक्टर्स और उनके पुरुष स्टाफ द्वारा किया जाता है, जोकि महिलाओं की आबरू को देखते हुए आपत्तिजनक है। मामले को गम्भीरता से लेते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने सीएमओ आदेश जारी किए हैं कि किसी भी महिला का पोस्टमॉर्टम अब पुरुष डॉक्टर्स द्वारा न कराया जाए। लेडी डॉक्टर्स ही महिलाओं के मृत शरीर का पोस्टमॉर्टम करें।

संविधान का अनुच्छेद 21 देता है महिलाओं को यह अधिकार

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने आदेश में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परमानन्द कटारा प्रति भारतसंघ एआईआर 1989 एससी 2033 में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार मात्र जीवित व्यक्तियों को ही प्राप्त नहीं है बल्कि यह मृत व्यक्तियों के शव के सम्बन्ध में भी लागू है। कोरोना काल में शवों के साथ अपमानजनक व्यवहार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी इसी आधार पर एडवाइजरी जारी की गई थी जो कि 14 मई 2021 के एफएन R-18/18/2020-PRP&P (RU-1) में दर्ज है।

न्यायोचित नहीं पुरुष डॉक्टर द्वारा महिला का पोस्टमॉर्टम

दरअसल पोस्टमॉर्टम की कार्यवाही में शव को सर्व प्रथम निर्वस्त्र किया जाता है। इसके बाद विच्छेदन की प्रक्रिया सम्पन्न होती है। इस कार्यवाही में पोस्टमॉर्टम गृह में केवल पुरुष वर्ग के डॉक्टर्स की उपस्थिति होती है, उनके साथ एक भी महिला नहीं होती है। यह संविधान प्रदत्त मूलाधिकार का उल्लंघन है। जीवित रहते जो कृत्य एक महिला के साथ सम्भव नहीं है, वह कृत्य मृत्यु के बाद उसके शव के साथ भी न्यायोचित नहीं है।

कोर्ट ने कहा है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के पास चिकित्सा सेवा संवर्ग की महिला चिकित्सक, फार्मासिस्ट आदि स्टाफ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आगे से आगरा में महिलाओं के पोस्टमॉर्टम में पुरुषों की संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। केवल महिला चिकित्सक व उनके महिला स्टाफ की देखरेख में ही कार्यवाही की जाए।

Amar Ujala

### **Kaithal News: सड़कों के लिए ठंड में आंदोलन जारी**

<https://www.amarujala.com/haryana/kaithal/movement-for-roads-continues-in-the-cold-kaithal-news-knl133379165-2023-01-15>

गुहला-चीका। हल्का गुहला की जर्जर सड़कों के विरोध में सड़क सुरक्षा मंच का क्रमिक अनशन शनिवार को 31वें दिन भी जारी रहा। शनिवार को गुलजार सिंह नंबरदार, नफे सिंह नंबरदार, सतपाल नंबरदार, मनीष कौशिक व गोपाल मेहरा क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे। इस मौके पर गुलजार सिंह नंबरदार ने कहा कि हल्का के लोग सड़कों की बदहाली के कारण अपने प्राण गंवा रहे हैं जबकि यहां के राजनेता अपना त्योहार मना रहे हैं। ठंड ज्यादा है लेकिन अनशनकारियों के हौसले में कोई कमी आई।

गांवों से लोगों का समर्थन सड़क सुरक्षा मोर्चा को लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने ने कहा कि कुरुक्षेत्र के सांसद धरना स्थल के पास से चुपचाप गुजर गए। उन्होंने अनशनकारियों से मिलने की कोई जहमत नहीं उठाई। गुहला में पिछले तीन साल से लोग सड़क निर्माण के लिए संघर्षरत है सड़कें बनना तो दूर उन पर पैच वर्क तक नहीं हुआ है।

मंच के सदस्य साहब सिंह संधू ने कहा कि सरकार ने सड़कों के मुद्दे पर जल्द कोई ठोस कारवाई न की तो टटियाणा स्थित टोल बैरियर को फ्री करवाएंगे। मंच के सदस्यों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं क्राइम कंट्रोल ब्यूरो हरियाणा को ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन में सड़क हादसों में लोगों के होने वाले जानमाल की हिफाजत सुनिश्चित करने की मांग की गई। इस मौके पर निर्जन गुर्जर, अमरेंद्र सिंह, नानक सिंह नंबरदार, कृष्ण नंबरदार, शेखर खट्टर, गुरसेवक सिंह, मोहन लाल भूना, नायब सिंह सीड़ा, जसवंत सिंह कांगथली, परमीश वर्मा, सुरजीत गुर्जर मौजूद रहे।